



ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY, PATNA

Established by the State Legislature Act. XXIV of 2008.

Mithapur, Patna - 800 001

Phone No.:0612-2351919, Email-akuniv10@gmail.com, Website: www.akubihar.ac.in

प्रेस विज्ञप्ति

मोनाश यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित त्रीदिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला में माननीय कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की भागीदारी

पटना (अप्रैल 10, 2024): आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो० शरद कुमार यादव ने दिनांक 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी में "Fight Against Online Child Exploitation" विषय पर आयोजित त्रीदिवसीय कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। इस कार्यशाला में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की प्रमुख रूप से सहभागिता रही।

कार्यशाला का समग्र लक्ष्य बाल शोषण की तकनीकी रोकथाम, ऑस्ट्रेलिया और भारत में संबंधित कानून प्रवर्तन पहलों की वर्तमान स्थिति को समझना और इस क्षेत्र में अनुसंधान सूचित नवाचार के साझेदारी मॉडल को विकसित करना है।

कार्यशाला के प्रथम दिन 8 अप्रैल को माननीय कुलपति प्रो० शरद कुमार यादव ने ऑनलाइन माध्यम से "Combating Child Sexual Abuse Material : A Call to Action" शीर्षक पर प्रस्तुति दी।

कार्यशाला के द्वितीय दिन 9 अप्रैल को कार्यशाला के शीर्षक से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों यथा कानून प्रवर्तन, सरकार, विनियमन और उद्योग तथा व्यवसाय, शिक्षा और समुदाय पर विस्तृत चर्चा हुई।

कार्यशाला के अंतिम दिन आज दिनांक 10 अप्रैल 2024 को माननीय कुलपति प्रो० शरद कुमार यादव ने कहा कि बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के प्रसार को रोकना एक बहुआयामी चुनौती है जिसके लिए शिक्षण संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, कानून प्रवर्तन, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता है। सीएसएएम रोकथाम के लिए चुनौतियों और अवसरों पर विचार करने से इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए रणनीतियों के निर्माण में मदद मिल सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसमें विभिन्न चुनौतियाँ आ सकती हैं। तकनीकी चुनौतियों में एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्म्स और अज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रसार ऑनलाइन सीएसएएम का पता लगाने और उसे हटाने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। एन्क्रिप्शन कानून प्रवर्तन और तकनीकी कंपनियों की सीएसएएम की पहचान करने और उसे रोकने की क्षमता में बाधा डाल सकता है, जिससे रोकथाम के प्रयास जटिल हो सकते हैं। ऑनलाइन प्रसारित सीएसएएम की विशाल मात्रा है, जिसे प्रभावी ढंग से पहचानना और हटाना मुश्किल हो जाता है। स्वचालित पहचान प्रणालियाँ मदद कर सकती हैं, लेकिन वे फुलप्रूफ नहीं हैं और इसके परिणाम गलत हो सकते हैं या सीएसएएम के नए और विकसित रूप छूट सकते हैं। सीएसएएम एक वैश्विक मुद्दा है, और क्षेत्राधिकार की सीमाएँ कानून प्रवर्तन प्रयासों में बाधा बन सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है लेकिन कानूनी ढांचे, सांस्कृतिक मानदंडों और संसाधन आवंटन में अंतर के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सीएसएएम के पीडितों को शर्मिंदगी और भय का सामना करना पड़ सकता है, जो उन्हें दुर्व्यवहार की घटनाओं की रिपोर्ट करने से रोक सकता है। इसके अतिरिक्त, कुछ व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हो सकते हैं कि वे सीएसएएम के शिकार हैं, जिससे रिपोर्टिंग और हस्तक्षेप के प्रयास और भी जटिल हो जाते हैं। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति, जैसे डीपफेक और आभासी वास्तविकता, सीएसएएम की रोकथाम के लिए नई चुनौतियाँ पेश करती हैं। इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग वास्तविक और नकली सामग्री के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है।

उन्होंने अनेक पहलों जैसे शिक्षा एवं जागरूकता अभियान, क्षमता निर्माण, सामुदायिक व्यस्तता, युवा सशक्तिकरण, मीडिया और मनोरंजन उद्योग, नीति वकालत, आदि पर भी अपना पक्ष रखा।



ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY, PATNA

Established by the State Legislature Act. XXIV of 2008.

Mithapur, Patna - 800 001

Phone No.:0612-2351919, Email-akuniv10@gmail.com, Website: www.akubihar.ac.in

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को जनवरी 2024 में बिहार में साइबर सुरक्षा पहल पर नॉलेज पार्टनर के लिए यूनिसेफ, बिहार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यूनिसेफ के द्वारा साइबर पीस फाउंडेशन और मोनाश यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया के साझेदारी में साइबर सुरक्षा और CSAM पर कार्य करने का पहल किया गया है। इस साझेदारी के माध्यम से AILECS लैब, मोनाश यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा विकसित तकनीक सीखने और इसे बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के साथ भारत के संदर्भ में अनुकूलित करने और सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद भारत के अन्य राज्यों में इसको लागू करने की परिकल्पना की गई है।

इस प्रोजेक्ट में बिहार पुलिस का साइबर अपराध शाखा, IIT, Patna चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तथा बीआईटी मेसरा, पटना भी कार्यान्वयन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कानूनी जागरूकता के लिए भागीदार तथा नॉलेज पार्टनर होंगे।

प्रस्तावित साझेदारी में प्रौद्योगिकी को समझने और सीखने के लिए मोनाश विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया में एक शिक्षण दौरा किया जा रहा है जिसमें बिहार का प्रतिनिधिमंडल शामिल है। इसके पश्चात ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के हितधारकों के द्वारा परामर्श के माध्यम से भारतीय संदर्भ - मुद्दों, साइबर सुरक्षा, सीएसएम पर चिंताओं को समझने और भारत में इस अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने, परीक्षण करने और स्केल-अप करने में उनके साथ काम करने के लिए भारत का दौरा भी किया जाएगा।

AILECS लैब, मोनाश यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफेसर कैंपबेल विल्सन, सह-निदेशक, ऐ-लिन सू संचालन प्रबंधक तथा प्रोफेसर जान राउज़ कार्यशाला में शामिल हैं।

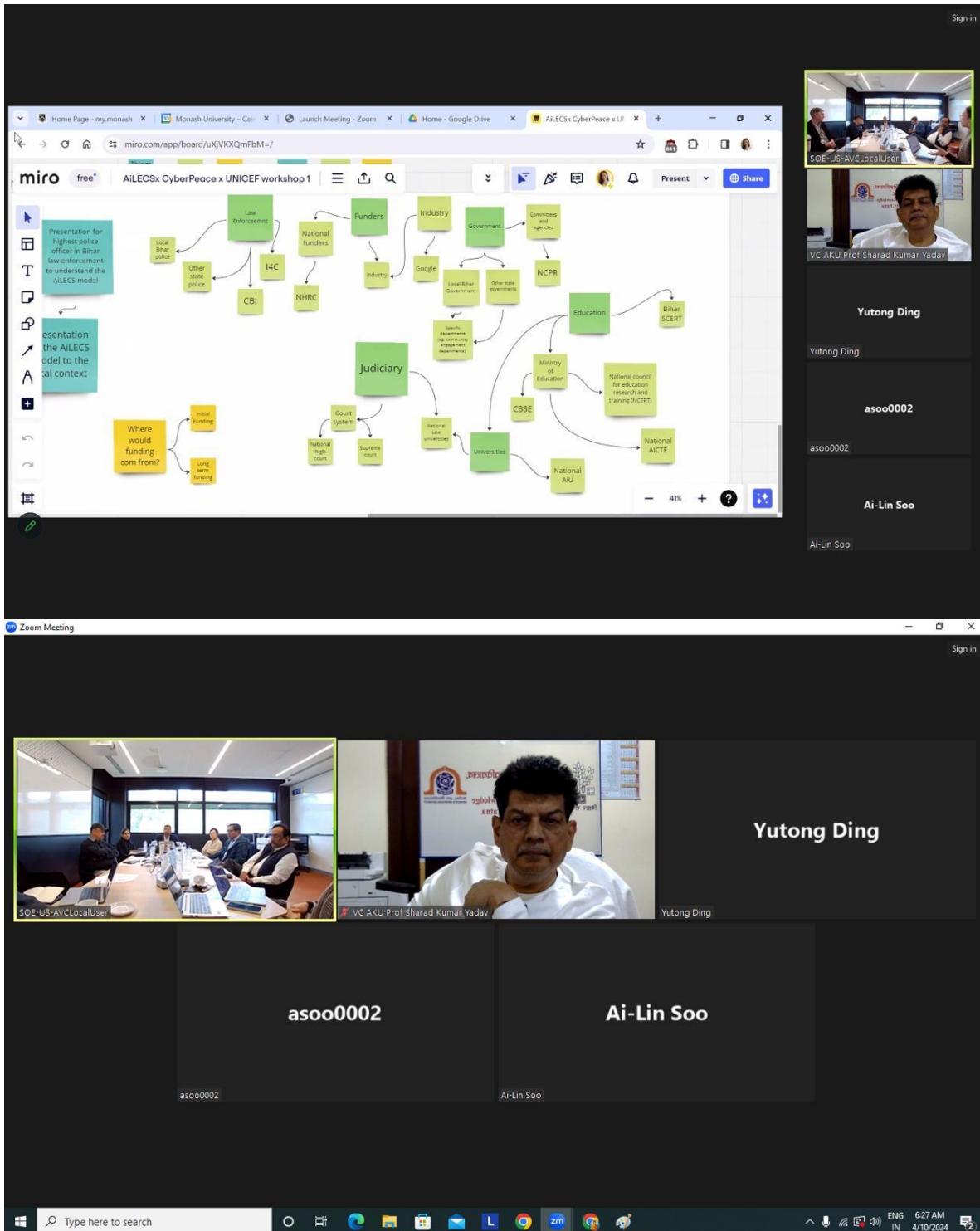


ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY, PATNA

Established by the State Legislature Act. XXIV of 2008.

Mithapur, Patna - 800 001

Phone No.:0612-2351919, Email-akuniv10@gmail.com, Website: www.akubihar.ac.in





ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY, PATNA

Established by the State Legislature Act. XXIV of 2008.

Mithapur, Patna – 800 001

Phone No.:0612-2351919, Email-akuniv10@gmail.com, Website: www.akubihar.ac.in

Zoom Meeting

Project Scope (1).pdf

PDF Reader Pro

Tools Page Edit Editor Converter Form Edit PDF Sign Redact OCR Page Display

My AI Credit

Sign in

Project Scope (1).pdf

PHASE 1 (0-6 months)

Establish the partnership and complete the design

Establish the partnership and scope key activities

Establish the foundational partnership with Monash University and CPF and scope out detailed design. Identify and engage with additional consortium partners. Organise a visit to India for the Monash University design team to work with CPC on the final project design and meet all the relevant stakeholders. Organise a stakeholder engagement workshop in India with all relevant law enforcement agencies and research institutions to co-design the project intervention. Map law enforcement agencies and relevant roles and responsibilities that will inform the final project design. Organise a visit to Australia for the Indian delegation to see the AILECS Lab firsthand and be introduced to the Australian model that will be carried out with the Australian Federal Police. Submit the final project design for the rollout in Madhya Pradesh.

PHASE 2 (7-15 months)

Launch research & deliver law enforcement knowledge sharing

Research

- Initiate research activities including algorithmic development and data curation.
- Prepare case studies to be presented in a dedicated workshop: Kerala Police Cyberdome (cyberdome.kerala.gov.in/) and the role of the Australian Federal Police (AFP) in sharing knowledge for initiative setup; the Australian Centre to Counter Child Exploitation (www.atcp.gov.au/what-we-do/operational-support/australian-centre-counter-child-exploitation).
- Rollout conferences and workshops.

Knowledge Sharing

- Within the agreed jurisdiction, assess key training needs and opportunities to shape knowledge sharing and capacity building activities.
- Develop training material by using what's available in India, and by contextualising and adapting (where agreed) AFP materials. Leverage existing collaborations with organisations such as INTERPOL and UNICRI for additional training resources.
- Train – using a blended model (in person and remote) – master trainers, potentially providing formal certification and creating a pathway for further certification such as a master's degree.

PHASE 3 (16-24 months)

Focus on research and community education, with refresher knowledge sharing

Establish the Center of Excellence

- Establish a dedicated CoE in collaboration with academics, law enforcement, and civil society, including the recruitment of key personnel (academics, PhD students, law enforcement officers, and civilian experts).
- Spread the model of CoE nodes across additional states and jurisdictions.

Research

- Ramp up research activities including algorithmic development and data curation.
- Convene conferences and workshops.

Knowledge Sharing

- Master trainers provide cascade training to all of the state's law enforcement officers.
- If new research is conducted, provide refresher training as needed.

Community Education

Run educational activities targeting schools to help children understand online dangers, by leveraging materials developed by CPF, such as its Cyber Safety Manual, and

Yutong Ding

asoo0002

asoo0002

Ai-Lin Soo

Ai-Lin Soo

Yutong Ding

VC AKU Prof Sharad Kumar Yadav

SOE-US-AVCLocalUser

Type here to search

Zoom Meeting

Sign in

7:30 AM ENG IN 4/10/2024

Yutong Ding

asoo0002

Ai-Lin Soo

Ai-Lin Soo

Yutong Ding

VC AKU Prof Sharad Kumar Yadav

SOE-US-AVCLocalUser

Type here to search

Zoom Meeting

Sign in

6:27 AM ENG IN 4/10/2024